आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मंगलवार 18.02.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू, विपक्षी सदस्यों ने सत्रावधि बढ़ाने की मांग को लेकर सदन में शोर–शराबा किया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन में ई–विधानसभा एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
- प्रदेश के 13 आईटीआई के उच्चीकरण के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू।

बजट सत्र

राज्य विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सदन में बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ये कानून लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार, विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखण्ड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में कई नये आयाम स्थापित किये गये। वहीं, राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने सत्रावधि बढ़ाने की मांग को लेकर शोर–शराबा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। इसलिए सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए, ताकि चर्चा के लिए जरूरी समय मिल सके।

ई विधानसभा एप्लीकेशन

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा भवन में ई–विधान एप्लीकेशन (NeVA) का लोकापर्ण किया। गौरतलब है कि इस बार राज्य विधानसभा का बजट सत्र नेशनल ई– विधान एप्लीकेशन के तहत संचालित किया जा रहा है। विधानसभा के कार्यों को डिजिटल और पेपरलैस बनाने के लिए ई–विधानसभा प्रणाली अपनाई गई है। इसके माध्यम से विधायकों को कार्यसूची, विधानसभा में पूछे गये प्रश्नों के जवाब और अन्य दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध कराये जायेंगे।

इसके तहत विधानसभा में विधायकों की टेबल पर टैबलेट लगाए गए हैं और सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि विधानसभा की कार्यवाही भी अधिक दक्षता से संपन्न होगी।

यातायात प्लान

राज्य विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए, देहरादून शहर के लिए यातायात प्लान जारी किया गया है। इसके तहत शहर में कई जगहों पर, रूट डायवर्ट रहेगा। विधानसभा सत्र के दौरान, जुलूस को रोकने और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रगति विहार, शास्त्री नगर, बाईपास, डिफेंस कॉलोनी और विधानसभा तिराहे पर बैरियर लगाये गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अलग कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किये गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को यातायात संबंधी कोई भी समस्या होती है, तो वे कंट्रोल रूम नंबर, 112 और यातायात कंट्रोल रूम नंबर 7 5 7 9 – 2 7 8 1 – 5 4 पर संपर्क कर सकते हैं। पुलिस द्वारा उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। परीक्षार्थियों को किसी भी दशा में नहीं रोका जायेगा। पुलिस प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को परीक्षा के लिए समय से रवाना करना सुनिश्चित करें।

मुख्य चुनाव आयुक्त

देश के निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे राजीव कुमार का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988–बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। वे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। वहीं, डॉ. विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा–1989 बैच के हरियाणा कैडर के अधिकारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की है।

एलिवेटेड कॉरिडोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को रिस्पना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर की बैठक में मुख्यमंत्री ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केन्द्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादून में आबादी और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि, पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि और दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद यातायात में संभावित वृद्धि के दृष्टिगत देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिये। गौरतलब है कि रिस्पना नदी के तल पर 11 किलोमीटर और बिंदाल नदी के तल पर 15 किलोमीटर लंबे चार लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य होना है। इन नदियों के अन्दर स्थित जन सेवाओं– विद्युत लाइन, हाई टेंशन लाइन, सीवर लाइन का नदी से बाहर विस्थापन भी होना है। एलिवेटेड रोड के साथ नदी के दोनों किनारों पर रिटेनिंग वॉल और बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा।

एमओयू

प्रदेश में युवाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा और इंडस्ट्री–रेडी ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से देहरादून में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग और टाटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू साइन किया गया है। विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस ऐतिहासिक समझौते के तहत प्रदेश के 13 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा। इससे छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं और नई तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने और उत्तराखंड को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नगर निगम देहरादून

देहरादून नगर निगम के मेयर, सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामी बंसल ने निगम परिसर से 15 इलेक्ट्रिक कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम की ओर से संचालित ये वाहन रिस्पना नदी किनारे स्थित मलिन बस्तियों से कूड़ा उठान का कार्य करेंगे। मेयर सौरभ थपलियाल ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की दिशा में निगम का यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
नगर आयुक्त नमामी बंसल ने बताया कि रिस्पना नदी क्षेत्र के आसपास आबादी क्षेत्र में सफाई जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नगर निगम, भविष्य में इन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है।

प्रधानमंत्री तैयारियां

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आगामी 27 फरवरी को प्रस्तावित मुखबा–हर्षिल कार्यक्रम को लेकर उत्तरकाशी जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सीमांत क्षेत्र के वाइब्रेंट विलेज– हर्षिल में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही हैं। मुखबा में पार्किंग, रास्तों के निर्माण और सौंदर्यीकरण से जुड़े कार्य कराए जा हैं। क्षेत्र में कूड़ा प्रबंधन और शौचालय व्यवस्था को लेकर भी काम किए जा रहे हैं। इस संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री के संभावित भ्रमण कार्यक्रम को लेकर सभी आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन पर प्रस्तावित कार्यक्रम समूचे राज्य के शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होंगे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग इसके लिए अपने मुख्यालय स्तर से समन्वय बनाकर सभी तैयारियां सुनिश्चित करें।